COAL INDIA LTD. organises
Essay Writing, Poster Making and
Quiz Competitions
on promoting integrity and moral values
at
NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY
31st July to 5th August 2023

सतर्कता

सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मुद्दों के अलावा मंत्रालय के सतर्कता प्रशासन की देखरेख करता है। मंत्रालय का सीवीओ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), डीओपीएण्डटी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों का समन्वय करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'शिकायत निपटान नीति' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (सीटीएस) का उपयोग करते हुए इन शिकायतों की प्राप्ति से लेकर इन पर सक्रिय, निवारक और दंडात्मक तरीके से कार्रवाई की जाती है जैसे औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच, अनुवर्ती जांच और कंपनी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए सीटीई प्रकार की परीक्षा।

शिकायतें सामान्यतरू संसद सदस्यों/विधायकों/कर्मचारियों और आम जनता से प्राप्त होती हैं। शिकायतों की प्रकृति मुख्य रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, निविदाओं में अनियमितताओं, मुआवजे के संबंध में कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के संबंध में होती हैं।

2. संगठन संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में अपर सचिव होते हैं। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता स्कंधों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के प्रमुख प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त सीवीओ होते हैं। उपर्युक्त संगठनों के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के संबंध में, सतर्कता संबंधी मुद्दों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता का मनाया जाना

दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे / Say no to corruption "Commit to the nation"** मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय में सत्यनिष्ठा शपथ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। सतर्कता मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए सभी कंपनियों में भी इसी तरह की गतिविधियां की गईं।

4. समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सीवीओ के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान 25.04.2023, 30.08.2023 और 30.11.2023 को तीन बैठकें आयोजित की गईं।

5. वर्ष 2023–24 के दौरान जारी प्रणाली सुधार उपाय

सभी संगठन अचल सम्पत्ति विवरणी (आईपीआर) को ऑनलाइन जमा करने, अधिकारियों के संवेदनशील से गैर. संवेदनशील पदों पर स्थानांतरण आदि में सक्रिय भागीदार हैं। इसके अलावा, 2023 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख प्रणाली सुधार के सुझाव दिए गए थे:

सीआईएल के प्रणालीगत सुधार उपाय

क) चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति: चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रणाली का अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि सीआईएल के ऑन–रोल कर्मचारियों के लिए मेडिकल बिलों (ओपीडी और आईपीडी) की जांच और भुगतान सीआईएल–मुख्यालय के वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त चिकित्सा बिलों को डॉक्टरों द्वारा जांच किए बिना अग्रेषित किया जाता है। इस प्रकार, दवाओं की स्वीकार्यता का निर्धारण करने की जिम्मेदारी वित्त कार्यकारी की है जो वित्त मैनुअल के अनुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे बिलों को पास करने के संबंध में कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध नहीं थी।

सतर्कता प्रभाग ने रियल टाइम बिल ट्रैकिंग के लिए ईआरपी पोर्टल में सभी बिलों की मैपिंग का सुझाव दिया है। बिल पास करने के लिए एसओपी तैयार करने का भी सुझाव दिया गया।

विभिन्न एसआईएम जारी किए गए थे जिनका विधिवत अनुपालन किया गया था।

ख) ई–एमबी और ई–बिलिंग पोर्टल

सीआईएल में ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ, ई–एमबी की अवधारणा को ईआरपी के लिए एक उपप्रणाली के रूप में फिर से देखा गया था। माप की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और बिलों की तैयारी समय पर भुगतान और परियोजनाओं के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए पसंदीदा तरीका है। यह निवारक सतर्कता के एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करेगा। डोमेन विशिष्ट बिजनेस लॉजिक सीआईएल और विभिन्न सहायक कंपनियों की एक बहु–विषयक इन–हाउस टीम द्वारा तैयार किया गया था। सीआईएल और सहायक कंपनियों के नए सौंपे गए कार्यों के लिए सीआईएल और सहायक कंपनियों के लिए पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। ई–एमबी पोर्टल पर पुराने अनुबंधों के माइग्रेशन की योजना सफल कार्यान्वयन के एक महीने के बाद बनाई जाएगी। अनुमोदित डीपीआर और विकसित पोर्टल की विशेषताओं के आधार पर कार्यान्वयन के बाद ई–एमबी पोर्टल के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 18.08.2023 को पोर्टल लॉन्च करने के बाद जारी की गई है। पोर्टल के लिए अधिदेश का शुभारंभ 04.11.2023 को किया गया था।

ग. एनआईटी/एलओए में उप–संविदा खंडों की समीक्षा: सेवा संविदा के उप–भाड़ा खंड के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में एक सहायक कंपनी में जांच के दौरान यह पाया गया कि एनआईटी और बाद में जारी किए गए एलओए के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी भी परिस्थिति में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उप–संविदा की अनुमति नहीं है। कार्य के निष्पादन के दौरान, मुख्य गतिविधि के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य उप–ठेके पर पाए गए थे।

इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्य की आवश्यकता के आधार पर, एनआईटी के नियमों और शर्तों का मसौदा तैयार करते समय विशेष ध्यान रखा जाए। सतर्कता जांच रिपोर्ट की जांच के बाद, सीवीसी की सलाह पर इसी प्रकार की निविदाओं में खंडों को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रणालीगत सुधार सुझाव जारी किए गए थे ताकि ठेकों की व्यावहारिकता बनी रहे।

घ) मानक एनआईटी दस्तावेजों में संशोधन: एक मामला जिसमें मानक बोली दस्तावेज, जिसे सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और सहायक कंपनी स्तर पर संशोधित किया गया था, की सीआईएल सतर्कता में जांच की गई है। बिल्ट ऑन ऑपरेट (बीओओ) आधार पर वाशरियों की स्थापना

के लिए मॉडल बोली दस्तावेज सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसने सहायक बोर्ड को मामूली संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए भी अधिकृत किया था।

प्रणालीगत सुधार उपायों के संबंध में सुझाव दिया गया था कि सहायक कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा मॉडल बोली दस्तावेज में किए गए किसी भी परिवर्तन के बारे में सीआईएल में समान रूप से इसकी प्रयोज्यता की जांच करने के लिए सीआईएल को सूचित किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि सीआईएल द्वारा कार्यों और सेवाओं की ई–खरीद के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में जहां तक संभव हो, स्पष्ट रूप से बड़े और छोटे बदलावों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बीओओ आधार पर वाशरियों की स्थापना के लिए मॉडल बोली दस्तावेज को अद्यतन करने का सुझाव दिया गया था क्योंकि बीओओ के लिए अंतिम मॉडल बोली दस्तावेज सीआईएल बोर्ड द्वारा 2015 में अनुमोदित किया गया था।

ङ) **अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना/पूर्व मंजूरी के बारे में एसआईएम:** संपत्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना/पिछली मंजूरी के लिए कार्यकारियों के लिए प्रक्रिया मैनुअल और पेपर–आधारित थी। इस पद्धति में दक्षता और पारदर्शिता का अभाव था। सीआईएल के वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) पोर्टल में इन सूचनाओं या प्रतिबंधों को दर्ज करने की सुविधा शामिल नहीं थी। मैन्युअल सबमिशन प्रक्रिया इसे बोझिल और समय लेने वाली बनाती है, जिससे जानकारी की ठीक से जांच करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, सीडीए नियमों के अनुपालन में पूर्व सूचना से संबंधित आवेदनों के ऑनलाइन जमा करने या अचल संपत्तियों के लिए पूर्व मंजूरी की मांग करने के लिए एक मॉड्यूल को शामिल करके एपीआर पोर्टल को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस संशोधन का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और प्राप्त संबंधित सूचना या मंजूरी के साथ वार्षिक रिटर्न में प्रत्येक प्रविष्टि को समेकित रूप से जोड़ते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रबंधन को सुझाव दिए गए थे जो अब कार्यान्वयनाधीन है।

च) **फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार पर प्रतिबंध:** यह पाया गया है कि सहायक कंपनियों द्वारा सूचित फर्मों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामलों से निपटने में सीआईएल में अत्यधिक विलंब हो रहा था। सीआईएल प्रबंधन को इस मामले में प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था।

जारी किए गए एसआईएम के बाद, सीआईएल प्रबंधन ने फर्मों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित क्रय नियमावली के प्रावधानों में संशोधन किया है। इन संशोधनों में उन विशिष्ट खंडों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत प्रतिबंध सीआईएल में समान रूप से लागू होगा या किसी विशेष सहायक कंपनी तक सीमित होगा। इसके अलावा, संशोधित प्रावधान अन्य सहायक कंपनियों से आचरण और कार्य–निष्पादन के आकलन के बाद अन्य सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध के विस्तार की अनुमति देते हैं। एक एसओपी जारी की गई है, जो सीआईएल के क्रय मैनुअल का एक हिस्सा भी है।

एनएलसीआईएल के प्रणालीगत सुधार उपाय

(क) **खान Iए, नेयवेली में ओवरबर्डन (ओबी) को हटाने के लिए आउटसोर्स संविदा कार्य।**

पाई गई विसंगतियां : उन क्रियाकलापों में अनुमत दर की तुलना में अनुमान में अनुमत मूल्यह्रास की उच्चतर दर, जिनमें एनएलसीआईएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले डीजल को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लगभग 200 मीटर तक दूरी में हुए प्रमुख बदलाव को राउंड ऑफ करना, प्रति शिफ्ट ओवरमैन/सरदार की अपेक्षित संख्या को नियोजित नहीं करना और ठेकेदार द्वारा कैंप कार्यालय के लिए उपयोग किए जा सकने वाले क्षेत्र की अनुमत सीमा विनिर्दिष्ट न करना।

सामने आए सुधार : मूल्यह्रास की दर पर भारत सरकार के नवीनतम परिपत्र के अनुसार अनुमान तैयार करना, एनएलसीआईएल द्वारा डीजल आपूर्ति के लिए अनुषंगी/सहायक कार्यकलापों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, राउंडऑफ के बिना दूरी में वास्तविक प्रमुख बदलाव को बनाए रखना, आवश्यक ओवरमैन/सरदार को काम पर न लगाने के लिए दंड को शामिल करना और कैम्प कार्यालय के लिए ठेकेदार को आबंटित क्षेत्र विनिर्दिष्ट करना।

(ख) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सीएसआर के तहत आयोजित चिकित्सा शिविरः

देखी गई विसंगतियांः सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल के जीएच द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों में किसी एसओपी का पालन नहीं किया गया और दोहराव और रिकॉर्ड के रखरखाव से बचने के लिए लाभार्थी के विवरण को कैप्चर नहीं किया गया। व्हील चेयर, श्रवण यंत्र और ट्राइपॉड जैसी चिकित्सा सहायक सामग्री एलटीई के माध्यम से प्राप्त करना न कि जीईएम के माध्यम से।

सुझाए गए सुधारः एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए एसओपी तैयार करना, चिकित्सा सहायता जारी करने के लिए उचित दस्तावेज और रिकॉर्ड रखना, दोहराव से बचने के लिए लाभार्थियों का आधार आधारित चयन और जीईएम के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्राप्त करना।

ग) एनएलसीआईएल भर्तियों में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों का सत्यापनः

अवलोकनः सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वास्तविकता की जांच करने का कोई चलन नहीं। लेटरल भर्ती के संबंध में फर्जी प्रमाण पत्र (सीटीसी दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र) के दो मामले पाए जाने के बाद भी मानव संसाधन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सुझाए गए प्रणालीगत सुधारः प्रमाणपत्रों के सत्यापन को अनिवार्य बनाना और सभी नए भर्ती हुए व्यक्तियों द्वारा जारी करने वाले अधिकारियों को प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को सत्यापित करना।

घ) डीजीएम/खनन (लेटरेल प्रवेश) की भर्ती के संबंध में पीआईडीपीआई शिकायतः

एक अतिरिक्त योग्यता के स्थान पर शैक्षिक योग्यता के भाग के रूप में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र की आवश्यकता का पाया जाना। सतर्कता विभाग की सलाह के आधार पर, मानव संसाधन विभाग ने एक परिशिष्ट जारी किया और विस्तारित समय–सीमा के साथ आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया।

ङ) ईएमडी/प्रतिभूति राशि की मात्रा की गणना

कुछ निविदाओं में जीएसटी को छोड़कर ईएमडी/प्रतिभूति राशि की गणना देखी गई। सतर्कता निष्कर्षों के आधार पर, अनुमानित मूल्य के साथ जीएसटी पर ईएमडी की गणना करने के लिए सभी इच्छुक प्रभागों को एक परिपत्र जारी किया गया था।

च) डिजाल्व ऑक्सीजन एनालाइजर की खरीद और जीईएम खरीद में अनापेक्षित विक्रेता पर विचार।

जीईएम में एलटीई के माध्यम से वस्तुओं की खरीद में मूल्यांकन के लिए अनापेक्षित विक्रेताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार न किया जाना पाया गया। सतर्कता अवलोकनों के आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अनापेक्षित विक्रेताओं पर विचार करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।

छ) स्थानीय खरीद (एलपी) के माध्यम से एनएलसीआईएल के जनरल अस्पताल द्वारा खरीदी गई दवाओं की प्राप्ति और जारी करने का लेखा–जोखा।

अवलोकनः एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (आईएचएमएस) में स्थानीय खरीद के माध्यम से खरीदी गई दवाओं का लेखा–जोखा न होना और

रोगियों को दवा की प्राप्ति के बारे में सूचित करने की कोई सुविधा नहीं होना। सतर्कता द्वारा सिफारिश की गई कि आईएचएमएस में एलपी दवाओं की प्राप्ति दर्ज की जाए और दवाइयां प्राप्त होने पर रोगी को एसएमएस के जरिए सूचित किया जाए।

ज) खान डंप क्षेत्रों में "अत्याधुनिक कृषि":

नेयवेली में सभी तीन खानों के माइंस स्पॉयल की उर्वरता बढ़ाने और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को रोजगार देने के घोषित उद्देश्यों के साथ 100 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक कृषि शुरू की गई थी। चूंकि निवेश पर प्रतिलाभ बहुत कम था और उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका, सतर्कता विभाग ने अत्याधुनिक कृषि परियोजना को बंद करने की सिफारिश की और इसका अनुपालन किया गया।

झ) पीआर विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्टॉलों की स्थापना के लिए कार्य संविदाएं प्रदान करने में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पीआईडीपीआई शिकायत;

अवलोकन: सूचीबद्ध एजेंसियों को स्टाल लगाने के काम में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था; एक विशेष फर्म का पक्ष लिया गया था और नामांकन के आधार पर काम आवंटित किया गया था; उपहार वस्तुओं को जीईएम के माध्यम से नहीं खरीदा गया था और उपहारों का कोई उचित लेखा–जोखा नहीं रखा गया था।

सुझाए गए सुधार: स्टाल लगाने का कार्य केवल खुली निविदा के रूप में जारी किया जाएगा एलटीई के मामले में, सूचीबद्ध एजेंसियों को आमंत्रित किया जाएगा और नामांकन से बचा जाएगा; भाग लेने वाली प्रदर्शनियों का वर्गीकरण करना और जीईएम के माध्यम से उपहार वस्तुओं की खरीद करना और उचित लेखांकन के लिए एक प्रणाली बनाना।

6. 01.01.2023 से 31.03.2024 तक शिकायतों, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति का विवरण

प्राप्त, निपटाए गए और लंबित शिकायतों तथा मामलों का विवरण (सामान्य/वीआईपी/पीआईडीपीआई/सीवीसी)

स्रोत	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाए गए	शेष	समय–वार लंबित मामले (माह)			
						<1	1-3	3-6	>6
सामान्य	29	503	532	519	13	0	13	0	0
वीआईपी	0	10	10	8	2	1	1	0	0
पीआईडीपीआई	0	10	10	5	5	3	2	0	0
सीवीसी (एफआर और आई एंड आर)	0	7	7	5	2	0	2	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण –प्रमुख

स्रोत	प्रारंभिक शेष	इस अवधि के दौरान आईओ को सौंपी गई पूछताछ	कुल	आईओ से प्राप्त रिपोर्ट	आईओ के पास लंबित पूछताछ	समय–वार लंबित मामले (माह)			
						<6	6-12	12-18	>18
प्रमुख शास्ति वाले मामले	4	1	5	3	2	1	0	0	1

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण–लघु

स्रोत	प्रारंभिक शेष	इस अवधि के दौरान डीए द्वारा लघु शास्ति का आरोप पत्र	कुल	ऐसे मामले जिनमें डीए द्वारा अंतिम आदेश जारी किए गए हैं	लंबित शेष	समय–वार लंबित मामले (माह)			
						<6	6-12	12-18	>18
लघु शास्ति वाले मामले	1	1	2	2	0	0	0	0	0

अभियोजन स्वीकृति का विवरण

प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल	मंजूरी दी गई	मंजूरी देने से इनकार किया गया	लंबित शेष
1	1	2	2	0	0